Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 8, Issue 1 | May. 2020 - October 2020 | pp. 20-25

भारत-नेपाल संबंध : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

डॉ. अनिल कुमार यादव

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन का उद्देश्य भारत नेपाल के ऐतिहासिक सम्बन्धों का अध्ययन करते हुए वर्तमान में दोनों राष्ट्रों के संबंधों में आई दरार के कारणों का विश्लेषण करना है। नेपाल के माध्यम से सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत को घेरने के चीनी प्रयासों का उल्लेख भी इस शोध पत्र में किया गया है। 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता की सन्धि का विश्लेषण करने के साथ-साथ भारत-नेपाल सम्बन्धों को प्रभावित करने में चीन की भूमिका का अध्ययन भी शोध पत्र में किया गया है। नेपाल में राजशाही की समाप्ति एवं सितम्बर 2015 में नये संविधान के लागू होने के पश्चात भारत-नेपाल सम्बन्धों में आए नए बदलावों की विवेचना भी शोध पत्र में की गई है।

संकेताक्षर : *बफर स्टेट, पीपुल्स वार ग्रुप, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, आर्थिक नाकेबंदी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी*

प्रस्तावना

भारत और नेपाल घनिष्ठ पड़ोसी राष्ट्र है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों के कारण नेपाल, भारत की विदेश नीति में भी विशेष स्थान रखता है। हिमालय पर्वतमाला एवं कई महत्वपूर्ण नदियां दोनों राष्ट्रों के मध्य साझी संपत्ति है साथ ही दोनों देश हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के सन्दर्भ में भी संबंध साझा करते है। महात्मा बुद्ध की जन्म भूमि नेपाल है तो उनका निर्वाण स्थल कुशीनगर (भारत) है। इन पारम्परिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को रक्त एवं वैवाहिक संबंध सदियों से पुष्ट करते रहे हैं। ब्रिटिश काल में जब लार्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था तब नेपाली लोगों ने भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी। नेपाल अकेला ऐसा विदेशी राष्ट्र है जिसके नागरिक भारतीय सेना में भर्ती किये जाते हैं। भारत में करीब छह मिलियन से ज्यादा नेपाली विभिन्न कार्यो में लगे हुए है। वे यहां बैंक खाता खोल सकते हैं और अपनी संपत्ति रख सकते हैं। दोनों देशों के बीच विद्यमान मुक्त सीमा ने लोगों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाया है।

संक्षेप में भारत एवं नेपाल के बीच बेटी-रोटी के संबंध है। नेपाल की हजारों लड़कियां भारत में ब्याही गई हैं और वे भारत में अपना घर बसाकर रह रही हैं। नेपाल के हजारों जवान भारतीय सेना में है। भारत ने सदैव नेपाल की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए उनके निराकरण हेतु हरसंभव प्रयास किये हैं। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में उतार-चढाव आते रहते हैं, बावजूद इसके परंपरा का सम्मान दोनों देशों के संबंधों में हमेशा मिठास घोलता आया है।

1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि

यह संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। यह दोनों देशों के मध्य एक द्विपक्षीय संधि है जो दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही, रक्षा एंव विदेशी मामलों में घनिष्ठ संबंध और सहयोग की अनुमति प्रदान करती है। संधि में कहा गया था कि ''कोई भी सरकार किसी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा एक-दूसरे की प्रतिरक्षा को पैदा किया जाने वाला खतरा बर्दाश्त नहीं करेगी और दोनों ही देशों के बीच संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कारणों के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

इस समझौते से दोनों राष्ट्रों के मध्य विशेष संबंध प्रगाढ हुए थे और भारत ने नेपालियों को भारतीयों के समान ही शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में प्राथमिकता वाला दर्जा देने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की थी जिस पर भारत आज भी कायम है।

साथ ही ''इस संधि के पीछे यह भावना थी कि भारत के लिए प्रतिरक्षा और प्रभाव की दृष्टि से नेपाल का महत्त्व है और नेपाल के लिए आर्थिक विकास और समुद्र तट के अभाव में आवश्यकता पूर्ति के लिए भारत का।''[1]

भारत -नेपाल संबंधों में तनाव के मुख्य मुद्दे

कुछ समय पूर्व तक दोनों राष्ट्रों के संबंध काफी हद तक ठीक-ठाक चल रहे थे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 2014 की नेपाल यात्रा एवं अप्रैल 2015 में नेपाल के भीषण भूकंप में भारत द्वारा की गई सक्रिय सहायता के बाद दोनों देशों के संबंध एक नई उंचाई तक पहुँचे थे परन्तु नेपाल द्वारा 2015 में नया संविधान लागू करने के पश्चात् दोनों देशों के मधुर संबंधों में खटास की शुरूआत हो गई। हालांकि इससे पूर्व भी कुछ मुद्दों पर दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव उभर कर सामने आये थे।

भारत-नेपाल संबंधों में तनाव का मुख्य कारण 1950 की शांति एवं मित्रता संधि है। नेपाल को लगता है कि यह समझौता गैर-बराबरी वाला है और उस वक्त किया गया था जब नेपाल कमजोर राष्ट्र था एवं अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाने में असमर्थ था। 70 के दशक में नेपाल ने मांग की थी कि 1950 में हुई शांति और मैत्री संधि की समीक्षा की जाए। 2008 में माओवादियों के नेतृत्व में अपनी लोकतांत्रिक सरकार का गठन होने के पश्चात नेपाल ने 1950 की भारत-नेपाल संधि को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे पूरी तरह खारिज करने की मांग की। इस संधि के नवीनीकरण के समय भी नेपाल ने कई आपत्तियाँ जताई और एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस नई संधि में नेपाल में निर्मित वस्तुओं को भारत भेजे जाने पर सीमा शुल्क नहीं देना होगा। संधि की इस व्यवस्था का नेपाल खुलेआम दुरूपयोग करता रहा है।

सन् 1988 में भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर नेपाल ने चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदे। मार्च 1989 में व्यापार एवं पारगमन संधि की अवधि समाप्त होने पर भारत ने इसके नवीनीकरण से इंकार कर दिया। कुछ आर्थिक मसलों को लेकर भी भारत-नेपाल संबंधों में कुछ तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद भारत ने सीमा जाँच, शुल्क इत्यादि के बारे में सख्ती बरतना शुरू किया। परिणामस्वरूप ''नेपाल में भारत विरोधी तत्वों ने भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि भारत नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी कर उसकी स्वतंत्रता और अखण्डता को सीमित करना चाहता है।''[2] साथ ही ''नेपाल ने जोर-शोर से यह घोषणा की कि नेपाल सम्प्रभु राष्ट्र है और भारत को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह चीन के साथ नेपाल के सम्बन्धों को लेकर नाक-भौंह सिकोड़े। नेपाल ने यह घोषणा करने में भी देर नहीं लगाई कि उसे अब भारत के साथ विशेष सम्बन्धों की कोई आवश्यकता नहीं है।''[3]

दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में खटास पैदा करने वाला एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा नदी जल विवाद भी है। भारत ने जब कोसी नदी पर बाँध बनाया तो भारत के खिलाफ नेपाल में काफी असन्तोष उत्पन्न हुआ ''नेपाली सरकार ने अपनी जनता को यह स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया कि उसने स्वेच्छा से बाँध की भूमि भारत सरकार को बेची है और बाँध से उत्पन्न होने वाली बिजली का लाभ भी संधि की शर्तों के अनुसार नेपाल को मिलेगा।''[4] अभी हाल ही में 22 जून 2020 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी कि नेपाल गंडक, ललबेकिया एवं कमला नदी के तटबंधों पर मरम्मत का काम नहीं करने दे रहा है, तो इसे नेपाल और भारत के रिश्तों में तनातनी के साथ-साथ बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ जाने के संदर्भ में देखा गया।

वर्तमान समय में दोनों राष्ट्रों के संबंधों में एक बड़ी चुनौती नेपाली माओवादियों का भारतीय नक्सलवादियों के साथ संबंध है। नेपाली माओवादी संगठन का भारत के माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पीपुल्स वार ग्रुप के साथ निकट संबंध है। इन नक्सलवादी संगठनों ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड एवं अन्य कई राज्यों में आंतक फैला रखा है।

दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए नेपाल में इस्लामिक चरमपंथियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. की भारत विरोधी गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। कई दशकों से न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान भी नेपाल की भूमि का उपयोग भारत विरोधी षड्यंत्र रचने के लिए करते आए हैं। जनवरी 2000 में काठमाण्डू से एक भारतीय यात्री विमान के अपहरण की साजिश के तार काठमाण्डू से कंधार और काबुल तक जुड़े.हुए थे। पाकिस्तानी आंतकवादी भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए अब नेपाल के रास्तें से भारत में प्रवेश करने लगे हैं। आज नेपाल आई.एस.आई. का गढ़ बन चुका है। यह बात जगजाहिर हो चुकी है कि नेपाल भारत विरोधी षड्यंत्रकारी तत्त्वों को मदद भले ही ना करता हो परन्तु उनकी अनदेखी अवश्य करता है।

नेपाल के माओवादी आन्दोलन के कारण भी दोनों राष्ट्रों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ है। माओवादियों एवं नेपाल में लोकतंत्र के समर्थकों को लगता है कि भारत सरकार राजशाही को समर्थन दे रही है। जबकि राजवंश को लगता है कि राजमहल के विरोधियों को भारत सहायता दे रहा है।

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को नेपाल

द्वारा जारी मानचित्र में नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाये जाने पर दोनों राष्ट्रों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ है।

मई 2020 को दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में गंभीर तनाव उस समय उत्पन्न हुआ जब भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सर्कुलर लिंक रोड़ का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह 'एकतरफा कदम' दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए बनी सहमति के खिलाफ है। भारत ने नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने जो सड़क बनाई है वह पूरी तरह से उसके क्षेत्र में है। भारत और नेपाल दोनों ही दावा करते हैं कि कालापानी उनके देश का अभिन्न अंग है। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है जबकि नेपाल उसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। इसी सन्दर्भ में ''दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा विवाद मई 2020 में उस समय पुन: उठ खड़ा हुआ जब नेपाल ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें तिब्बत, चीन व नेपाल की सीमा से सटे भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख एवं लिंपियाधूरा सहित 372 वर्ग किमी. क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया गया।''[5] इसी के मद्देनजर नेपाली संसद में भी एक संविधान संशोधन विधेयक जून 2020 में पारित किया गया जिसमें इन क्षेत्रों को नेपाल के भाग के रूप में दर्शाया गया। नेपाली संसद को सम्बोधित करते हुए नेपाली प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा 'ओली' ने इन क्षेत्रों को वापस लेने के लिए मजबूत कूटनीतिक कदम उठाने की बात कही।

हालिया महीनों में (जून-जुलाई 2020) भारत की ओर से नेपाल सीमा के पास सड़क निर्माण के कार्य की वजह से भी दोनों देशों में तनाव बढ़ा है।

''12 जून 2020 को भारत-नेपाल बॉर्डर पर बिहार के सीतामढ़ी के जानकीनगर के पास नेपाली पुलिस द्वारा भारतीयों पर बेवजह फायरिंग की गयी जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए।''[6]

आजकल नेपाल का आग्रह है कि नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि नेपाल ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण उपमहाद्वीप को ही शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। नेपाल की यह मांग अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर यह दोषारोपण है कि भारत नेपाल के लिए खतरा है। सम्भवत: नेपाल को शान्ति क्षेत्र घोषित कराने के पीछे नेपाल का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रभाव और विशिष्ट स्थिति को नकारना है जिसे नेपाल अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व की खोज में बाधक समझता है।

संक्षेप में नेपाली प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा ओली के भारत विरोधी बयानों और वहाँ राजनीतिक उठा-पटक, भूमि-विवाद को लेकर नेपाली संसद में संविधान संशोधन, सीमा पर झड़प, आशंकाओं की धुंध में हेलीपेड एवं रास्तों का निर्माण, भारतीय बहुओं के लिए नेपाली नागरिकता की नई समय सीमा तय करने, पिथौरागढ़ में काली नदी का पुल बंद किए जाने और सबसे ज्यादा ताजा नेपाल द्वारा चीन को अपनी जमीन भेंट करने जैसी खबरें दोनों देशों के आपसी ऐतिहासिक रिश्तों के लिए शुभ संकेत नहीं है।

के.पी. शर्मा 'ओली' और भारत-नेपाल संबंध

सन् 2015 में नेपाल में नए संविधान के लागू किये जाने के पश्चात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के के.पी.शर्मा 'ओली' प्रधानमंत्री बने लेकिन जुलाई 2016 में जब सहयोगी दलों ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया तो ओली सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तब ओली ने भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

नए संविधान को लेकर मधेशी एवं थारू समुदाय के अल्पसंख्यक लोगों ने और अधिक अधिकारों की माँग को लेकर आन्दोलन किया एवं भारत-नेपाल सीमा को बंद कर दिया। भारत ने भी नए संविधान को लेकर नेपाल के समक्ष अपनी आपत्ति जताई। भारत का कहना था कि नए संविधान में मधेशी और थारू समुदाय के लोगों की मांग को शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप भारत की ओर से नेपाल को पेट्रोल, दवाइयाँ और दूसरे कई तरह के सामान की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। नेपालियों ने इसे भारत द्वारा नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी की संज्ञा दी। 135 दिनों तक चली इस आर्थिक नाकेबंदी ने दोनों देशों के संबंधों में खटास घोल दी जिसके परिणामस्वरूप नेपाल में भारत विरोधी भावनाएँ उत्पन्न हुई और इसी भारत विरोधी भावना के कारण ही 2017 के आम चुनावों में के.पी.शर्मा ओली नेपाल के दुबारा प्रधानमंत्री बने। ओली को चीन समर्थक माना जाता है। ओली 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि के मुखर आलोचक रहे हैं। ओली समय-समय पर भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। अभी हाल ही में (जून 2020) उन्होंने बयान दिया कि भारत से गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोग नेपाल में कोविड-19 वायरस फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'भारत का वायरस चीन और इटली से भी ज्यादा खतरनाक है।' भारत के हितों को नजरअंदाज करते हुए ओली सरकार चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना के साथ है। ओली चाहते हैं कि चीन तिब्बत के साथ-साथ नेपाल में भी सड़क मार्गों का निर्माण करे ताकि भारत पर नेपाल की निर्भरता कम हो सके। हाल ही में जब ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एवं सरकार के सहयोगी दलों ने ओली के इस्तीफे की माँग की तो

ओली ने भारत पर आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए भारत एवं काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।

भारत-नेपाल संबंधों में चीन की भूमिका

भारत एवं चीन के मध्य नेपाल 'बफर स्टेट' के रूप में अवस्थित है। चीन की 1236 किमी. एवं भारत की 1690 किमी. सीमा नेपाल के साथ लगती है। अत: भारत एवं चीन दोनों ही देशों के लिए नेपाल का अत्यधिक सामरिक महत्त्व है। चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण के पश्चात् चीन के लिए नेपाल के सामरिक महत्त्व में और अधिक वृद्धि हुई है। चीन के लिए भारत का बढ़ता प्रभाव रणनीतिक एवं सुरक्षागत कारणों से, विशेषकर तिब्बत के मद्देनजर गंभीर चिंता का मुद्दा है। दक्षिण एशिया में शक्ति सन्तुलन को अपने पक्ष में कायम रखना चीन की नेपाल नीति का मुख्य सामरिक लक्ष्य रहा है। ''नेपाल का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना ताकि इसके दुश्मन चीन विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए इस देश का इस्तेमाल ना कर सके, नेपाल में चीन का प्राथमिक रणनीतिक लक्ष्य है।''[7]

भारत के विरुद्ध सन्तुलन बनाये रखने हेतु चीन, नेपाल में दखल की नीति अपनाए हुए है। चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण के पश्चात् से 'बफर स्टेट' की भूमिका नेपाल को प्राप्त हुई और भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह नेपाल में चीन की सीधी पहुँच को रोके। आज नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के परिणामस्वरूप पिछले कुछ समय से दोनों देशों के संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही है। चीन ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया है। ''दूसरी तरफ नेपाल की भी भारत के विरुद्ध चीन से लाभ उठाने की प्रवृत्ति रही है।''[8] भारत-नेपाल के आपसी संबंधों में चीन ने सदैव अवरोधक की भूमिका निभाई है। ''नेपाल में चीन की गतिविधियां भारत विरोधी और ध्वंसात्मक रही है साथ ही चीन अपने प्रभाव विस्तार के लिए नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को निरन्तर प्रोत्साहन दे रहा है। अत: नेपाल में यह विचार बल पकड़ने लगा है कि उसे भारत और चीन के मध्य एक अवरोधक (बफर) राज्य की भूमिका निभानी चाहिए।''[9] भारत ने नेपाल के आन्तरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया अपितु नेपाल को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रचूर मात्रा में आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इसके बावजूद नेपाल का चीन की ओर झुकाव बढ़ता गया। भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए राजा महेन्द्र ने चीन के साथ काठमाण्डू-ल्हासा सड़क मार्ग बनाने हेतु समझौता किया। 1962 में भारत पर चीन द्वारा किये गये आक्रमण के प्रति नेपाल का तटस्थ भाव एक प्रकार से चीन का परोक्ष रूप से समर्थन ही था। एवरेस्ट पर्वत के संबंध में चीन-नेपाल में प्रारम्भिक समझौता भारत के प्रति विश्वासघात था। 1988 में नेपाल ने भारत सरकार से सलाह मशवरा किये बिना चीन से हथियार खरीदे तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नेपाल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर पाबन्दी लगा दी थी, क्योंकि नेपाल नरेश ने चीन से हथियारों की खरीद उस समय की जब नेपाल में आपातकाल लागू किया गया। फरवरी 2005 में नेपाल में राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने और राजा द्वारा संसदीय सरकार को भंग करने एवं राजा द्वारा माओवादियों के खिलाफ कार्यवाही का चीन ने समर्थन किया। सन् 2005 में चीन और नेपाल के बीच स्थापित कूटनीतिक संबंधों की 50 वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2005 में जकार्ता में आयोजित आसियान सम्मेलन में राजा ज्ञानेन्द्र एवं चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओं की मुलाकात हुई एवं हू जिंताओं ने नेपाल को चीन का स्वाभाविक एवं सदाबहार मित्र कहा। अगस्त 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल की दो दिवसीय यात्रा की। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने एवं भारत के पक्ष में नेपाल में भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने आसान शर्तों पर नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रूपये की सहायता देने की घोषणा की, साथ ही भारत की ओर से नेपाल में सड़क एवं इंटरनेट सेवाओं का जाल बिछाने में सहयोग देने की पेशकश की। ''परन्तु 28 अक्टूबर 2015 को चीन-नेपाल में सम्पन्न 'पेट्रो चाइना' समझौते के माध्यम से ड्रैगन ने कूटनीति के मोर्चे पर भारत को पटखनी दी है। ''इस समझौते ने साबित कर दिया है कि भारत को अपनी नेपाल नीति पर फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है।''[10]

चीन-नेपाल सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ अप्रैल 2017 का संयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसे 'सागरमाथा मैत्री' के नाम से जाना जाता है। यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और नेपाल आर्मी (एनए) के बीच पहला अभ्यास था। जून 2017 में भारत-चीन के मध्य शुरू हुए डोकलाम विवाद के दौरान चीनी उपप्रधानमंत्री वांग यांग ने नेपाली सरकार को तटस्थ बनाए रखने के उद्देश्य से नेपाल की यात्रा की। ऐसा लगता है कि काठमाण्डू ने इस दबाव का पालन किया जो कि नेपाल-चीन संबंधों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।

बीते 10-12 साल में नेपाल में भारत की साख में काफी गिरावट आई है। भारत पर आरोप लगते हैं कि वह नेपाल की राजनीति को 'माइक्रो मैनेज' कर रहा है। भारत के हस्तक्षेप को नेपाल के लोग अच्छा नहीं समझते। चीन तिब्बत से लेकर लुंबिनी तक रेल मार्ग का विस्तार करना चाहता है जिसे नेपाल अपने विकास के लिए आवश्यक मानता है। नेपाल वर्ष 2017 में चीन की 'वन

बेल्ट वन रोड परियोजना' में शामिल हुआ, परन्तु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल नहीं होने के लिए दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस तरह से दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना ने भारत की 'बिग ब्रदर' वाली छवि को स्थापित किया। अप्रैल 2018 में नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने पद सम्भालने के पश्चात् अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। ओली की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ''मैं इस बार हमारे रिश्तों को 21 वीं सदी की वास्तविकता के आधार पर नई ऊंचाई पर ले जाने के रास्ते तलाशने का मिशन लेकर भारत आया हूँ।'' वही भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मई 2018 में अपनी दो दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान कहा कि 'भारत की पड़ोसी नीति में नेपाल सबसे पहले आता है।

इन सबके बावजूद हाल ही में 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 80 किमी. लंबी सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज करायी। नेपाल का दावा है कि यह सड़क उसके क्षेत्र से होकर गई है। नेपाल इस बात से इतना खफा हुआ कि उसने कालापानी के करीब छारूंग में सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी। नेपाल ने ऐसे वक्त पर, जबकि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद अत्यधिक चरम पर है एवं सीमा पर दोनों देशों की फौजें आमने-सामने है, सुरक्षा बलों की तैनाती की, वो भारत के लिए असहज करने वाला रहा है। सीमा विवाद के सन्दर्भ में नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने नेपाल के अखबार 'राइजिंग नेपाल' को दिए इंटरव्यू में तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो नेपाल की सेना लड़ने के लिए तैयार है। भारत-नेपाल सीमा विवाद पर भारतीय मीडिया एवं अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ऐसे कदम उठा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ''नेपाल ने किसी और की वजह से अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है।'' इस बयान को चीन के दखल से जोड़ा गया और भारत में कुछ राइट् विंग मीडिया चैनलों ने सीमा विवाद उठाने के मामले में नेपाल को ''चीन की प्रॉक्सी' तक कह दिया। यह बयान नेपाल के लोगों को पसन्द नहीं आया। चीन के इशारे पर काम करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा ओली पर हाल ही में चीन से करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हाल ही में आई रिर्पोट के मुताबिक ओली ने चीन को नेपाल में अपना बिजनेस प्लान लागू करने की मदद करने की एवज में भारी भरकम राशि रिश्वत के रूप में ली है।

आज ''इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है कि चीनी खुफिया एजेसियां नेपाल में भारत की ताकत को काउंटर करने के लिए माओवादियों को न केवल भारत के खिलाफ भड़काती है बल्कि उन्हें आवश्यक ऊर्जा और पोषण भी उपलब्ध कराती है।''[11] ऐसे कई खुलासे भी सामने आए हैं जो बताते है कि नेपाल में चीनी धन का उपयोग भारत विरोधी मुहिम में किया जाता है। संक्षेप में ''चीन की नेपाल नीति तिब्बती स्थिरता से संबधित घरेलू सुरक्षा चिंताओं और भारत के प्रभाव को नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित है। इस बाबत नेपाल ने एक घरेलू हैजिंग (Hedging) की रणनीति अपनाई है।''[12]

अगर नेपाल चीन के साथ भारत को काउंटर बैलेंस करने की सहमति नहीं देता है तो चीन नेपाल की अस्पष्टता और भारत के साथ निरंतर भागीदारी से नाराज हो सकता है। वही अगर भारत को लगेगा कि उसका पारंपरिक मित्र चीन की और झुक रहा है तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। इन जटिल परिस्थितियों के मद्देनजर नेपाल को एक नाजुक बैलेंसर की भूमिका निभानी चाहिए।

भारत-नेपाल संबंधों में सुधार हेतु सुझाव

नेपाल के लोगों के मस्तिष्क में विद्यमान भारत की बड़े भाई की छवि को भारत को उदार एवं सकारात्मक बनानी होगी, साथ ही भारत को यह दिखाने की कोशिश भी करनी होगी कि वह वास्तव में नेपाल की लोकतांत्रिक महत्वकांक्षाओं और राजनीतिक गरिमा का हितैषी है।

नेपाल को भी यह ध्यान में रखना होगा कि उसका स्वाभाविक मित्र कौन है? उसे अपने भूगोल के सामरिक महत्त्व के आधार पर भारत पर अनुचित दबाव की नीति से परहेज करना होगा।

दोनों राष्ट्रों को अपनी सीमा, नदी जल विवाद सहित अन्य समस्त विवादों का समाधान राजनीतिक सूझबूझ एवं आपसी समझ के आधार पर करना चाहिए।

दोनों ही राष्ट्रों को मिल जुलकर एवं आपसी सहयोग से माओवादियों पर लगाम लगाने एवं उन्हें सीमित करने में सहयोग करना चाहिए।

हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारत-नेपाल संबंधों का मुख्य आधार है। नेपाल की करीब 94 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है, ऐसे हिंदू बहुल राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना सीधा-सीधा थोपा गया निर्णय प्रतीत होता है। नेपाल के विकास के लिए एवं उसे पुन: हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

नेपाल की भूमि का दुरूपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं हो सके, इसके लिए दोनों देशों को संयुक्त गश्त एवं निगरानी हेतु सहयोग करना होगा।

भारत, नेपाल सीमाएँ किसी प्राकृतिक अवरोध से विभाजित नहीं है। अत: इसकी बाड़बन्दी करके पूर्ण चौकसी हेतु दोनों राष्ट्रों का सहयोग अपेक्षित है।

भारत को अपने खिलाफ बने चीन-नेपाल-पाकिस्तान के गठजोड़ की काट ढूंढनी होगी जो दक्षिण एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

भारत एवं चीन के साथ नेपाल एक मंझे हुए सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है, परिणामस्वरूप चीनी निवेश के सामने भारतीय चमक फीकी पड़ रही है। लिहाजा भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा।

नेपाल में भारतीय सहयोग से चल रही विकास की परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि विकास परियोजनाओं के माध्यम से चीन भारत के पड़ोसी देशों में पहुँच स्थापित कर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहता।

भारत को नेपाल के प्रति अपनी विदेश नीति को दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक नीति को उपयोग में लाये जाने से पहले उसके रणनीतिक नफा-नुकसान पर विचार करना चाहिए।

भारत-नेपाल संबंधों का आधार पंचशील, समानता, परस्पर सम्मान एवं पारस्परिक लाभ हो।

भारत को नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग देना होगा क्योंकि स्थिर एवं विकसित नेपाल ही भारत के साथ स्थाई मित्रता और विश्वास को बनाये रखने में सहयोग दे सकता है।

भारत को गंभीर एवं सुलझे हुए प्रयासों के जरिए नेपाल सहित अपने सभी पड़ोसियों को साधने की आवश्यकता है ताकि चीन द्वारा पड़ोसी देशों में घुसकर भारत के लिए खतरा उत्पन्न करने की मंशा को नाकाम किया जा सके।

निष्कर्ष

विगत कुछ दशकों से नेपाल में भारतीय नीतियों एवं व्यवहार को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति, आकार एवं शक्ति के मद्देनजर कुछ हद तक ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इसके लिए अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं से नेपाल को अवगत कराते रहने के साथ-साथ भारत को अपने व्यवहार एवं कार्यो में नेपाल की सम्प्रभुता के प्रति सम्मान की भावना भी दिखानी होगी। भारत को नेपाल में चीन के स्वाभाविक एवं वैध हितों को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से चीन की सक्रियता एवं भारतीय सुरक्षा हितों के बीच एक लक्ष्मण रेखा अवश्य खींचनी पड़ेगी। नेपाल में शांति एवं स्थिरता कायम होने के पश्चात् आर्थिक विकास फिर से रफ्तार पकडेग़ा और नेपाली समाज में व्याप्त विषमता के कम होने के साथ-साथ भारत के प्रति शत्रुता एवं वैमनस्यता की भावना भी धीरे-धीरे ही सही पर कम अवश्य ही होगी। अत: नेपाल के प्रति भारतीय विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि नेपाल के साथ हमारे संबंध सहयोगी एवं मित्रवत् बने रहे। ऐसे संबंध न केवल भारत के पड़ोस में शांति एवं स्थायित्व कायम करेंगे बल्कि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओझा, शीला, ''समकालीन भारतीय विदेश नीति'' भाग-1, श्याम प्रकाशन, जयपुर, 2005, पृ.सं. 117
2. शर्मा, प्रभुदत्त, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-सिद्धान्त एवं व्यवहार'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2010, पृ.सं. 408
3. पंत, पुष्पेश, जैन, श्रीपाल एवं पंचौला, राखी, ''अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-सिद्धान्त व्यवहार'', मीनाश्री प्रकाशन , मेरठ, 2016-17, पृ.सं. 440
4. पंत, पुष्पेश, ''21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', चतुर्थ संस्करण, एमसीग्र हिल एजूकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2015, पृ.सं. VII.40
5. प्रतियोगिता दर्पण, अतिरिक्तांक, समसामयिक वार्षिकी 2020, वोल्यूम-2, पृ.सं. 164
6. राजस्थान पत्रिका, 13 जून 2020
7. पंत, हर्षवर्धन, ''भारतीय सुरक्षा एवं विदेश नीति'', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 147
8. दीक्षित, जे.एन., ''भारतीय विदेश नीति'', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1999, पृ.सं. 383
9. शर्मा, मथुरालाल एवं नाटाणी, प्रकाश नारायण, ''विदेश नीतियाँ'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2005, पृ.सं. 198
10. फड़िया, बी.एल. एवं फड़िया, कुलदीप, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', साहित्य भवन आगरा, 2016, पृ.सं. 327
11. कुमार, सतीश एवं कुमार, बजरंग, ''21वीं सदी में भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ-आंतरिक एवं बाह्य'', मोहित पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2015, पृ.सं. 287
12. साउथ एशियन वॉइस-दक्षिण एशिया में चीन नेपाल में बढती निकटता, 20 अक्टूबर 2017 (अवसना पांडे)